भारतीय सांख्यिकी संस्थान की प्लैटिनम जुबली के अवसर पर प्रधानमंत्री का भाषण

दिनांक 24 दिसम्बर, 2006
कोलकाता

मुझे आज यहां इस महान संस्थान की प्लैटिनम जुबली के अवसर पर उपस्थित होकर वाकई खुशी हो रही है। अर्थशास्त्र का एक विद्यार्थी होने के नाते मैं यह समझता हूं कि 'उबाऊ विज्ञान' कहे जाने वाला अर्थशास्त्र, सांख्यिकी का कितना ऋणी है, विशेषकर ऐसे समय में जब यह सिद्ध हो चुका हो कि कोई भी चीज वस्तुतः इतनी उबाऊ नहीं होती। आज शायद ही शिक्षा का कोई ऐसा विषय होगा जो किसी न किसी तरह से सांख्यिकी का ऋणी न हो। इसमें चाहे औषधि विज्ञान, इंजीनियरी, वित्त, सामाजिक विज्ञान, मानविकी हो अथवा सूचना प्रौद्योगिकी।

पचहत्तर साल पहले भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर प्रसातों चन्द्र महलानोबिस ने जो दीप जलाया था वह आज भी लगातार जल रहा है। भारत के जिन प्रतिष्ठित सांख्यिकीविदों ने यहां अध्ययन और अध्यापन किया है, उनमें प्रोफेसर जे.एन. सेनगुप्ता, एच.सी.सिन्हा, आर.सी.बोस तथा सी.आर.राव जैसे कुछेक नाम शामिल हैं जिन्होंने सांख्यिकी के विषय को समृद्ध बनाने में बड़ा भारी योगदान दिया है। मैं उनकी स्मृति को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान अकेला एक ऐसा संस्थान है जो प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के आंकड़ों के अनुसंधान, शिक्षण और प्रयोग को समर्पित है। इसकी इस भूमिका को मान्यता देते हुए इसकी 1959 में संसद के एक अधिनियम द्वारा 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' के रूप में घोषणा की गई। हमारे देश में राष्ट्रीय महत्व के कई संस्थानों की तरह भारतीय सांख्यिकी संस्थान भी नेहरू युग के दौरान फूला-फला। हम इसका श्रेय पंडितजी की सोच और नेतृत्व को देते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत में बौद्धिक प्रयासों की आधारशिला रखने में मदद की। उन्होंने अनेक महान अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षकों को समय और अवसर उपलब्ध कराए जिन्होंने इस प्रक्रिया में अपना योगदान दिया ।

भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रो0 महलानोबिस दूरदृष्टि रखने वाले विचारक थे। उन्होंने प्रभावी नीति निर्माण में सांख्यिकी और सांख्यिकीय विश्लेषण तथा अनुसंधान के महत्व को समझा। इसलिए यद्यपि संस्थान ने सैद्धांतिक अनुसंधान के क्षेत्रों में प्रगति की लेकिन प्रो0 महलानोबिस ने सांख्यिकीविदों को अनुप्रयोग दक्षता हासिल कराने के लिए प्रशिक्षण के महत्व को भी पहचाना।

जूट की फसल के अनुमानों में सुधार लाने के लिए 1937 के पूर्वार्द्ध में प्रो0 महलानोबिस के तकनीकी मार्गदर्शन में भारत में पहला अन्वेषणात्मक नमूना सर्वेक्षण शुरू किया गया। इस अध्ययन की रोनाल्ड फिशर द्वारा भूरि-भूरि सराहना की गई। उन्होंने तत्कालीन सरकार को ऐसे अध्ययनों के महत्व पर जोर देते हुए लिखा, "....... सब कुछ सांख्यिकी संस्था के भविष्य पर निर्भर करता है।"

संस्थान ने विशेषकर बंगाल में आर्थिक और सामाजिक हालात से जुड़े कई और नमूना सर्वेक्षण किए। संस्थान द्वारा फसल पैदावार अनुमान पर किए गए नवीन कार्य ने पंडित जवाहर लाल नेहरू का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या की स्थिति से जुड़ी व्यापक जानकारी चाही। वे देशव्यापी आधार पर नमूना सर्वेक्षण कराना चाहते थे।

इस प्रकार सन 1950 में प्रथम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण किया गया जो अब एक बृहत कार्य है। आज राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के तहत लगभग 2.5 लाख परिवार शामिल हैं और यह नमूना सर्वेक्षण तकनीक की प्रभाविकता का एक ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण है जिसके द्वारा कम लागत पर विश्वसनीय सूचना प्राप्त की जा सकती है। खपत, रोजगार और परिसंपत्तियों के बारे में समय-समय के विस्तृत और तुलनात्मक आंकड़े इससे प्राप्त किए जा सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रो0 महलानोबिस को केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अवैतनिक सांख्यिकी सलाहकार के रूप में आमंत्रित किए जाने से भारतीय सांख्यिकी संस्थान राष्ट्रीय आयोजना और नीति निर्माण संबंधी कार्यकलापों में और करीबी से जुड़ गया।

1950 और 1960 के दशक हमारे विकास के इतिहास का एक अलग ही दौर था। सरकार में बैठे अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के विद्वानों के बीच बड़ा संपर्क बना रहता था। दिल्ली स्कूल आफ इकॉनामिक्स और भारतीय सांख्यिकी संस्थान जैसे संस्थानों तथा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच प्रतिभाओं का आदान-प्रदान होता रहता था। इस संपर्क से शैक्षिक अनुसंधान का स्तर बढ़ा और यह अधिक नीतिपरक बना, साथ ही सरकार के भीतर भी एक रचनात्मक सोच विकसित हुई।

भारतीय सांख्यिकी प्रणाली जिसके निर्माण के पीछे बड़े-बड़े व्यक्तियों का हाथ रहा है और जिनमें कई भारतीय सांख्यिकी संस्थान से भी करीबी से जुडे रहे, से आज कई विकासशील देशों को ईर्ष्या होती है। भारत उन कुछेक विकासशील देशों में से एक है जो आई एम एफ के विशेष आंकड़ा प्रसार मानकों के अनुशासन के अनुरूप है जिसके तहत भारत अर्थव्यवस्था के वास्तविक, वित्तीय और बाह्य क्षेत्रों से संबंधित अनेक क्षेत्रों में नियमित रूप से गुणवत्ता युक्त आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

सन् 1949 में राष्ट्रीय आय समिति, 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और 1951 में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन और 1970 में एन.एस.एस.ओ. की स्थापना भारतीय सांख्यिकी प्रणाली के विकास में एक महत्वपूर्ण संस्थागत उपलब्धि है। हमारे पास एक बड़ी तथा विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था के लिए कई प्रकार के आंकड़े प्राप्त करने हेतु एक व्यापक बुनियादी ढांचा उपलब्ध है।

लेकिन, प्रशासनिक ढांचे और पराम्परागत रिकाड्र्स के ऊपर ज्यादा निर्भर रहने के कारण यह प्रणाली समय के बदलाव के साथ चलने में विफल रही है। उदारीकरण से भी अर्थव्यवस्था में भी काफी ढांचागत बदलाव आए हैं। ये ऐसे बदलाव हैं जिनके अनुरूप सांख्यिकी प्रणाली को अपने आपको ढालने की जरूरत है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद से प्रभावशाली और सराहनीय प्रगति के बावजूद हमारे सांख्यिकी आंकड़ों की विश्वसनीयता, समयावधि तथा विशुद्धता के बारे में काफी चिंताएं देखी गई हैं। महत्वपूर्ण आंकड़ों में बार-बार संशोधन से विश्वसनीयता और भी कम हुई है।

आर्थिक सिद्धांत ज्यादा से ज्यादा एक जैसे बदलावों के बीच संबंध स्थापित कर सकता है। लेकिन नीति निर्माताओं के लिए हमें इस संबंध का परिमाण निर्धारित करने की जरूरत है। इसके लिए समय-समय पर विश्वसनीय आंकड़ों की जरूरत होगी। सांख्यिकी अनुमान किसी भी अनुप्रयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेकिन यदि मूल आंकड़े गतल हों अथवा यथाथथ्य न हों अथवा विश्वसनीय न हों तो अनुमान व्यर्थ चला जाएगा।

मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि आंकड़ों की गुणवत्ता की चिंता भारत में कोई अलग या नई बात नहीं है। ब्रिटिश इंडिया के समय एक न्यायाधीश का उदाहरण हमारे सामने है जिसने एक अति उत्साही नौकरशाह जो उन्हें सरकारी आंकड़े बता रहा था, को फटकार लगाते हुए कहा था, “सरकारें आंकड़े इकट्ठा करने की बहुत इच्छुक रहती हैं, वे इन्हें एकत्र कर सत्ता के सम्मुख रखती हैं, उनका गुणा-भाग कर शानदार रूपरेखाएं तैयार करती हैं। लेकिन, आपको यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि इनमें से हरेक आंकड़ा सबसे पहले गांव के उस चौकीदार से मिलता है जिसे जैसा अच्छा लगता है लिख देता है।”

हाल के वर्षों में ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कई देशों ने अपनी सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार लाने पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार लाने के अपने प्रयासों में "सांख्यिकी में विश्वास बढ़ाना " के विचार को प्रमुखता दी है। भारत में आंकड़ों की गुणवत्ता संबंधी प्रश्नों के अलावा, डाटा अंतर, पुनरावृत्ति जिससे परस्पर-विरोधी आंकड़े मिलते हैं और आंकड़ों को भेजने तथा उनके प्रकाशन में अत्यधिक विलम्ब जैसी समस्याएं भी हैं।

उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में फलों, तरकारियों तथा अन्य लघु उपजों के उत्पादन तथा मांस उत्पादों एवं मछली के अनुमानों में काफी अंतर होता है। इसके अलावा, फसलों के आंकड़ों की गुणवत्ता में गिरावट की निरंतर समस्या भी है। एक नीति निर्माता होने के नाते मुझे गेहूं और गन्ना जैसे महत्वपूर्ण फसल उत्पादों के अनुमानों के बारे में विरोधात्मक आंकड़ों से दो-चार होना पड़ा है।

जहां तक उद्योगों का संबंध है, औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक हमारे जीवंत लघु क्षेत्र और औपचारिक क्षेत्र पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाने में नाकाम रहा है। हालांकि सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का अभी 60 फीसदी है लेकिन यह भी हमारी राष्ट्रीय आय संबंधी सांख्यिकी में पूरी तरह से अपनी पकड़ नहीं बना पाया है। क्षेत्र की व्यापकता, इसकी विषम प्रकृति, इसके तेजी से बदलते आकार जिसमें नई सेवाओं का उभरना और पुरानी सेवाओं का हटना शामिल हैं, को देखते हुए यह काम काफी कठिन हो जाता है।

दो अलग-अलग स्रोतों के एक ही परिवर्तन के अनुमानों में अंतर होना दूसरा प्रमुख मुद्दा है। उपभोग व्यय के बारे में राष्ट्रीय लेखा और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुमानों के बीच अंतर एक ऐसा उदाहरण है जो प्रायः देखने को मिलता है। मौजूदा प्रणाली मूल सामाजिक-आर्थिक संकेतकों जो सूक्ष्म स्तरीय योजना बनाने में महत्व रखते हैं, के बारे में भी प्रर्याप्त जानकारी दे पाने में विफल रही है। हमारी अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा के कई पहलुओं के संबंध में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

इसी तरह, वित्तीय बाजारों के अविनियमन से तेजी से वित्तीय प्रक्रिया में नवीनता आई है और गुणवत्तायुक्त वित्तीय आंकड़ों को नियमित और समय पर हासिल करने की जरूरत महसूस

हुई है। हाल के वित्तीय संकट के संदर्भ में वित्तीय आंकड़ों से संबंधित परम्परागत मुद्दों जैसे आंकड़ों को समय पर उपलब्ध कराना, उनकी यथाथथ्यता, पारदर्शिता, सामंजस्य, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मकता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव का आबादी के विभिन्न हिस्सों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। समय-समय पर कीमतों और उनकी दरों में बदलाव का मापन लगभग सभी आर्थिक मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यह गरीबी को मापने के लिए मौद्रिक नीति के लिए जरूरी होता है। इसलिए कीमतों के आंकड़ों में किसी भी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए और इन्हें बदलते उपभोग के पैटर्न के अनुसार होना चाहिए। उदाहरणार्थ, सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है इसलिए, सेवाओं के लिए एक अलग मूल्य सारिणी की संगणना की तत्काल जरूरत है।

इन कमियों को दूर करने के लिए भारतीय सांख्यिकी प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने और इसके बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने की जरूरत है। डॉ0 सी.रंगराजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने इन मुद्दों का अध्ययन करके इस जरूरत पर बल दिया कि हमारी आंकड़ा प्रणाली की विश्वसनीयता, समय और पर्याप्तता में सुधार किया जाए। इस समिति ने कई सुझाव दिए जिनमें भारतीय सांख्यिकी प्रणाली के गठन में सुधार लाना तथा इसके बुनियादी ढांचे का उन्नयन करना शामिल है ताकि आंकड़ों को एकत्र करने, आंकड़ों के एकत्रीकरण हेतु वैकल्पिक तकनीकों का पता लगाने, ऐसे नए आंकड़ों को चिह्नित करने जो बदलती अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर तैयार किए जा सकें, और जरूरत के अनुसार नए आंकड़ों को एकत्र करने के समुचित तरीके ढूंढ़ने में स्वायत्तता और सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

हमारी सरकार पारदर्शिता और खुलेपन में पूरी तरह से विश्वास रखती है। इसके लिए विश्वसनीय और समय पर उपलब्ध आंकड़ों की जरूरत है। तदनुसार हमने सभी महत्वपूर्ण सरकारी सांख्यिकीय कार्यकलापों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नामक एक नोडल निकाय स्थापित किया है। प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रो0 सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित इस नए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने इस साल जुलाई से अपना काम शुरू कर दिया है।

यह वाकई बड़े ही गर्व की बात है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने सामाजिक, प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञानों के साथ अपने संबंधों को निरंतर बढ़ाया है। इसने सरकार, उद्योगों, चोटी के अनुसंधानकर्ताओं, उच्च स्तर के शिक्षकों और प्रेरणा से ओत-प्रोत विद्यार्थियों के बीच सार्थक बातचीत के लिए एक शानदार मंच प्रदान किया है। मैं यहां के फैकल्टी और यहां आने वाले आगंतुकों के स्तर के बारे में बताना चाहूंगा। किसी भी संस्था के लिए जे.बी.एस.हाल्डेन और जॉर्ज अकरलोफ जैसी हस्तियों की मेहमाननवाजी करना वाकई एक बहुत बड़ी बात है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के लिए यह और भी उल्लेखनीय बात है कि इसने युवा प्रतिभाओं को विदेशों में आकर्षक नियुक्तियों पर जाने से रोका है। एक अर्थशास्त्री के रूप में, मैं इस बात से काफी प्रभावित हुआ हूं कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कौशिक बसु, टी.एन.श्रीनिवासन तथा बी.एस.मिन्हास जैसे श्रेष्ठ समकालीन भारतीय अर्थशास्त्रियों के साथ करीबी से जुड़ा हुआ है। मुझे बताया गया है कि गणित और सांख्यिकी इकाइयां भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। यह हम सभी के लिए बड़े ही गर्व की बात है।

हाल के वर्षों में इस संस्थान का आयोजना प्रक्रिया तथा देश की सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करने में सहयोग कम हुआ है। संस्थान को चाहिए कि वह भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की गुणवत्ता को बढ़ाने में न केवल सहयोग करे बल्कि इसमें प्रमुख भूमिका निभाए। संस्थान को उन क्षेत्रों में अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है जो नीति निर्माण विशेषकर सरकारी सांख्यिकी के क्षेत्र से संबंधित हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के तकनीक उन्नयन में मदद करनी चाहिए। इसे नमूना सर्वेक्षण विधि में सुधार लाना होगा और इसके लिए आंकड़ों को एकत्र करने की तकनीकों को अद्यतन तथा नवीन बनाना होगा और मुख्य कार्मिकों को उनके संगठनों में सांख्यिकी तरीकों से प्रशिक्षण देना होगा।

संदर्श आयोजना और सर्वेक्षण डिजाइन का जो कार्य विगत में संस्थान को सौंपा गया था उसकी जगह कोई और ऐसा ही कार्य उसे नियमित आधार पर नहीं दिया गया है। देश की सांख्यिकी प्रणाली में सुधार लाने के लिए ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिससे कि संस्थान को सरकारी आंकड़ों के एकत्रीकरण, संकलन और विश्लेषण में शामिल सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग की अनुमति मिल सके। संस्थान एक सरकारी सांख्यिकी इकाई की स्थापना करने पर भी विचार कर सकता है जो अनुसंधान के मामले में भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अनुसंधान कर्ताओं और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के बीच समन्वय स्थापित करेगी। इसके साथ ही यह संस्थान, सरकारी और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के सांख्यिकीविदों के बीच सरकारी आंकड़ों से संबंधित विषयों पर मिलजुलकर अनुसंधान में सहायता देने पर भी विचार कर सकता है।

आई.आई.टी. तथा आई.आई.एम जैसे अन्य अग्रणी शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों की तरह इस संस्थान को भी देश के दूसरे हिस्सों में भी अपनी स्थिति दर्ज करनी चाहिए ताकि देश की बढ़ती जरूरतें पूरी हो सकें। यह उचित समय है जब संस्थान को इस बारे में सोचना है।

मूल समस्याओं पर वैयक्तिक एकेडेमिक कार्यो और देश की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं से जुड़े कार्यों के बीच उचित संतुलन बनाने की जरूरत है।

मुझे आशा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान सरकारी सांख्यिकी प्रणाली में सुधार लाने और इस विषय के उत्तरोत्तर विकास में अपना निरंतर सहयोग देता रहेगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान को विश्व स्तर के एक श्रेष्ठ संस्थान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करना होगा। आज के युग में यदि किसी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है तो वह ज्ञान के क्षेत्र में है और इसीलिए हमें भारतीय सांख्यिकी जैसे उत्कृष्ट संस्थानों की जरूरत है। मुझे यकीन है कि 75 साल पहले प्रो0 महलानोबिस ने सांख्यिकी का जो दीप जलाया था वह भविष्य में भी निरंतर जलता रहेगा।

मैं आप सभी के और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। मुझे यकीन है कि आप इससे भी अच्छा कर दिखाएंगे।

....